

## प्रसंगवशा

ओंकारेश्वर पांडेय

शों की तबाली अचानक नहीं होती। न कोई रात में उठकर यह घोषणा करता है कि संविधान मर चुका है, और न कोई सुबह अखबार के पहले पन्ने पर यह लिखता है कि न्यायपालिका का अंत हो गया। यह सब धीरे-धीरे होता है। परत दर परत, साल दर साल, जब तक एक दिन ऐसा नहीं आता कि बची-खुची संस्थाएँ स्वयं ही स्वीकार कर लें कि अब प्रतिरोध संभव नहीं।

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जिन दो खसमे सम्मानित न्यायाधीशों जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस औरंग मियाह्वान ने एक-एक कर अपने पद से इस्तीफा दिया, वह भी एक साधारण विरोध नहीं है; यह पाकिस्तान की न्यायिक स्वतंत्रता की लाश पर लिखा गुथल-धुलान का अंतिम बयान है। लेकिन इस उथल-पुथल को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। यानी फ़ैजाबाद धरना, नवंबर 2017। वही धरना, वही जुमह, जो आठ साल बाद संविधान की कसबाह तक पीछा आता को खींच लाया। फ़ैजाबाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावपिंडी को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका और चौक (इंटरचेंज) है। 2017 की ठंडी नवंबर की एक सुबह इसी मोड़ पर एक ऐसा राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसे पाकिस्तान का रुख बदल दिया।

नवंबर 2017 में, एक धार्मिक-राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने इस चौक को पूरी तरह बंद कर दिया। उन्होंने राजधानी के आवागमन को ठप्प कर दिया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP), एक कट्टर धार्मिक-राजनीतिक संगठन,

अचानक राजधानी के दरवाजे पर खड़ा था। हज़ारों लोगों के साथ। पूरा देश एक ऐसे टकराव में डूबा हुआ जिसमें हर कोई जानता था कि सरकार की नहीं, किसी और की परीक्षा हो रही है।

कहा गया कि चुनाव अधिनियम की 'खुब-ए-नवत' की शायद में बदलाव ने यह तूफान खड़ा किया- परन्तु वह कोई धार्मिक अवस्था नहीं था, यह एक संदेश था। एक चेतावनी कि अगर सत्ता भूल जाए कि असली मौलिक कानून है, तो 'सड़कें' उसे याद दिलाने आ सकती हैं। शाहिद ख़ान अब्बासी की सरकार इस संकेत के सामने पिछल थी। जब सरकार गिरने जैसी हालत में थी, तब मंच पर प्रवेश हुआ पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली संस्थान का। ISI और MI के कुछ वज्र अधिकारी, जिन्होंने उस समय के DG-MI लोएतुद्द नज़र आमिर मुनीर भी शामिल थे, 'बातचीत' के लिए धरने में पहुँचे। और फिर वह दुख्य जिसे पाकिस्तान आज भी यूयूब पर बार-बार देख रहा है: वहीँधारी अधिकारी प्रदर्शनकारियों में लिफाफे बाँट रहे थे। सौदे तय किए जा रहे थे। धार्मिक उन्माद का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा था। सरकार ने घुटने टेक दिए। कानून मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। टेलीवीज विजयी होकर पर लौटी। हर किसी ने समझ लिया कि अरल सत्ता किसके हाथ में है।

दो साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जस्टिस काजीर जासकि ईसा की 2019 ने फैजुबाद धरने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वह पाकिस्तान की सत्ता संरचना के केंद्र पर सजिकल स्ट्राइक थी। जजों ने लिखा कि खुफिया एजेंसियों ने संविधान से परे जाकर काम किया। उन्होंने "अदृश्य हस्तक्षेप" को बेनकाब किया। कई अधिकारियों का नाम सीधे-सीधे दहल हुआ। दायरे में DG-ISI, DG-भूमिका पर कड़े टिप्पणी हुई। कथुं में DG-ISI, DG-

AI और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की प्रवेश भूमिका आ गई। और यहाँ से कहानी की दिशा बदल गई। यह फैसला पाकिस्तान की सैन्य-न्यायिक राजनीति के नियमों के विरुद्ध था। यह वह साहसिक कदम था जो 2007 के वकील आंदोलन की याद दिलाता था। लेकिन इस बार प्रतिद्वंद्वी भी अधिक शक्तिशाली, अधिक रणनीतिपूर्ण और अधिक छुपा हुआ था। नेता जो तय था: ऐसी न्यायपालिका दोबारा नहीं रहने दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं है फैजबाद मामले की स्वतः सुनवाई की। फैसले में न केवल साफ कहा- सेना और खुफिया एजेंसियाँ ने 'गैर-रिजिस्टर' और 'असंवैधानिक' भूमिका निभाई। उन्होंने एक 'अघोषित' भूमिका निभाकर लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर किया। यह फैसले ने दिखा दिया कि जब देश की प्रथाओं का बंधन नहीं हुई थी, तो असली सौदेबाजी राजधानी कार्यालय में नहीं, बल्कि सेना प्रमुखों और TLP नेताओं के बीच हो रही थी। जनरल आसिम मुनिर (अब सेना प्रमुख) और उनके संस्थान के लिए यह फैसला एक शर्मिंदगी और जख्म का कारण बना। आज 2025 में, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने वाला 27वाँ संशोधन, उसी जख्म का बदला माना जा रहा है। सेना प्रमुख एक ऐसी न्यायपालिका नहीं चाहते, जो उनके काम में देखी दे सके। 2024 में आठ 26वाँ संशोधन यानी पहला वार। यह न्यायपालिका की सामूहिक ताकत को कमजोर करने का प्रयोग था। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने वह उम्मीद की थी कि 'भौत से' प्रतिरोध होगा। पर हवा का रुख तेजी से बदल रहा था। 2025 का 27वाँ संशोधन तो विध्वंस का अंतिम चरण था। इसने सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में बाँट दिया, एक 'अपॉलीटाइज्ड' और एक नया 'संवैधानिक न्यायालय' जिसमें राज्यों की नियुक्ति पर कार्यपालिका का भारी प्रभाव रहेगा।

यह संविधान क भीतर रेंगता हुआ तबूतयापलट था, एक 'कानूनी' कू। इसके खिलाफ जस्टिस मंफूर प्रली शाह को इस्तीफा एक बेहद शर्म, सटीक, कानूनी अला शाह-उन्होंने कहा, 'एक फटे-पटे न्यायालय में बने रहना संविधान के अपराध में मौन साझेदारी है।' एक न्यायाधीश जो संविधान की रक्षा न कर सके, वह न्यायाधीश रह भी कैसे सकता है? जस्टिस अतार मिनहख़ा के पत्र उससे भी अधिक तीखा, मानवीय और झकड़ोरे देना पला था। उन्होंने लिखा: 'वह संविधान जिसे मैंने बचाने की शायश ली थी, अब अस्तित्व में ही नहीं है।' और फिर वह लौटें, जो पाकिस्तान की न्यायपालिका एक एक स्याह रेखा खींच देता है- 'अब न्यायाधीश का वस्त्र पहनना विश्वासघात का प्रतीक बन चुका है।' ये इस्तीफे नैकरियायें से त्यागपत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र के शव पर लिखे अंतिम शब्द हैं। आज का पाकिस्तान एक अधिक परिष्कृत, अधिक नियंत्रित, अधिक तकनीकी तंत्र है, जहाँ सत्ता गहरूम से नहीं, कानूनी संशोधनों और राजनीतिक मंचन से चलाई जाती है। जनरल आरिफ़ मुनीर, न पूरे संविधान को संक्रमित कर दिया है। अब कोही न्यायालय प्रश्न नहीं पूछेगा। अब कोही फैसला सत्ता को चुनौती नहीं देगा। अब पाकिस्तान में संविधान नहीं, बल्कि उसकी यादें बची हैं।

इस संविधान संशोधन के खिलाफ देश भर के वकीलों के संगठन और विपक्षी दल सड़कों पर उतर रहे हैं। इसे 'न्यायपालिका की हत्या' का नाम दिया जा रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाएगा, जहाँ लोकतंत्र का अंतिम गढ़ भी ढह गया। पाकिस्तान एक नए अधरे में प्रवेश कर चुका है, और पूरी दुनिया खामोश खड़ी देख रही है।

( सत्य हिंदी में प्रकाशित  
लेख के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छतरपुर में होटल द राजगढ़ पैलेस का शुभारंभ किया।

# टूरिस्ट हेली सर्विस का उठाएं भरपूर लाभ

- सालभर में 13.41 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश आए ● प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को दी वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की सौगात ● भारत में चिन्हित की गई 17 आइकोनिक सिटीज में खजुराहो भी शामिल ● राजगढ़ पैलेस होटल के जरिए स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार



कहा है कि विश्व  
को के लिए सभी  
पोर्ट तो पहले से  
नई वंदे भारत ट्रेन  
इवदे सिधे काशी

को की सुविधाओं है। इसके अलावा सुविधा भी मिलेगी डॉ. यादव ने प्रतिशत से अधिक पर्यटकों मध्य प्रदेश राज्य भविष्य में यह खजुराहो में एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक श्री वीडी शर्मा ने कहा कि खजुराहो एक विश्व धरोहर प्रमाणिक श्री मोदी ने भारत में खजुराहो भी शामिल है। यहां न केवल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों द्वारा सेवा के साथ सुपरफास्ट है। पन्ना में हीरो तो मिलते ही हैं डायमंड बनकर उभरेगा।

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| होटेल ड ओबेरॉय     | कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण |
| त शुरुआत किया।     | श्री अरविंद पटेलिया, विधायक   |
| ने पुष्पगुच्छ एवं  | शुक्ला, विधायक श्री कामाख्या  |
| अभिर्नन्दन किया।   | विद्या अग्निहोत्री, अपर मुख्य |
| ष आशीर्वाद प्राप्त | शुक्ला, डा आईजी विजय खत्री,   |
| खजुरीहो समृद्धि    | श्री आमा जैन सहित स्थानीय उ   |
| न विकास के लिए     | उपस्थित रहे।                  |

# करंट से किसान दंपति की मौत

**थावर नदी में मोटर हटाते समय हादसा  
पति को बचाने में चपेट में आई महिला**

**मंडला (नप्र)।** मंडला जिले के पिंडई चौकी क्षेत्र में बुधवार को पानी की मोटर निकालते समय करंट लगने से एक दंपति की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। हादसे से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

नदी में उतरकर मोटर निकाल रहे थे- जानकारी के अनुसार, ग्राम अतरिया निवासी केसान राधे कुलस्ते (36) और उनकी पत्नी सीमा कुलस्ते (30) की थावर नदी में करंट लगने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राधे कुलस्ते नदी में उतरकर मोटर निकाल रहे थे, तभी मशीन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई।

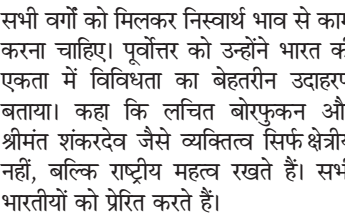
## दोनों की मौके पर मौत

इसके चलते पानी में तेज करंट फैल गया और राधे इसकी चपेट में आ गए। पति को बचाने की कोशिश में पत्नी सीमा भी नदी की ओर दौड़ी, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आकर मौके पर ही गिर पड़ी। इस दौरान दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

# भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है

- भागवत बोले-देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू ● कहा-  
यह शब्द धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपरा

**गुवाहाटी (एजेंसी)।** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा- भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि जो भी भारत पर प्रहार करता है, वह हिंदू है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यता गत पहचान है, जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। संघ चीफ सोमावार को तीन दिवसीय यात्रा के लिए असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। बुधवार को भागवत ने एक युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद 20 जनवर्बर को मणिपुर के लिए रवाना होंगे। असम में डेमोग्राफिक चेंज पर मोहन भागवत ने कहा- हमें आत्मविश्वास, सतर्कता और अपनी जमीन-संस्कृति से मजबूत लगाव रखना चाहिए। साथ ही कहा कि समाज के



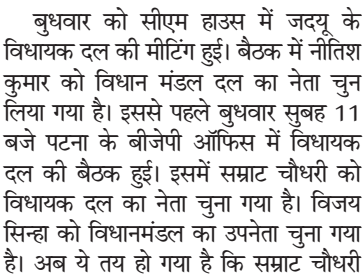
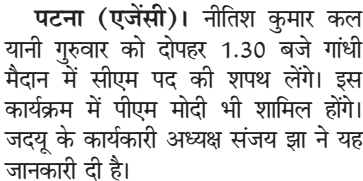
## शरद की सुबह

आज यह जो आम का पौधा लगाया है मैंने  
जब तक देह देगी साथ  
सनेह सीझूँगा इसे  
किसी दिन धरा के वक्ष पर  
वृक्ष बनेगा यह  
मोक्ष नहीं  
हर बार लौटने को जीवन् चाहूँगा मैं  
किसी शाख पर कूक भरूँगा कोयल बन  
तोता-चिड़िया बनकर चखूँगा  
चाहूँगा जितने फल  
लौटा यदि लेकर यही देह  
बैठूँगा इसकी ही छाँव में  
इसी के फल होंगे मेरी चाव में शामिल  
अब तो आज भूलने लगा हूँ कल का  
फिर किसे याद रहता है  
जन्म-जन्मांतर  
मैं सचमुच भूल जाऊँगा  
यहाँ आम का पौधा लगाया था मैंने

- वसंत सकरगाए

# नीतिश सीएम, सम्राट और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम

- बिहार में हो गया फैसला, शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 1.30 बजे



और विजय सिन्हा ही नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। इधर, सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने एलजीएम में 2 मंत्री पद और डिप्टी सीएम पद की डिमांड रखी है। चिराग अपने बहनोई अरुण भारती का नाम बढ़ा सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में एलजीएम (आर) ने 19 सीटें जीती हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले केन्द्रीय पर्यवेक्षकों ने आपस में चर्चा की।



## लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया

- बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला के मर्डर का लगा है आरोप



मुंबई/नई दिल्ली (एजेंसी)। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। उसे एयरपोर्ट से सीधे पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं। अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल, 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। वह पिछले साल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है।

## भारत को एसयू-57 फाइटर जेट्स देने को रूस तैयार

- तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेगा



मॉस्को (एजेंसी)। भारत को एसयू-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए रूस तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रॉस्टेक के सीईओ सेर्गेई केमेजोव ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। रूसी एसयू-57 जेट्स को अमेरिका के एफ-35 का तोड़ माना जाता है। एसयू-57 की तरह एफ-35 भी 5वीं जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका लंबे समय से भारत को एफ-35 बेचना चाह रहा है। रूस से यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं।

## एसआईआर के लिए गांव-गांव घूम रहे एसपी विधायक फहीम

- यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खिलाई थी बीवी की कसम



मुरादाबाद (एजेंसी)। बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी साल मॉनसून सत्र में यूपी विधानसभा में बहस के दौरान यूपी जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पत्नी की कसम खाने की चुनौती दी थी। सपा के तेज तर्रार नेता फहीम इरफान इस समय अपने क्षेत्र में गांव-गांव साइकिल से टहल रहे हैं। यह एसआईआर को लेकर उनका मतदाताओं को जागरूक करने का अपना तरीका है। अपने इस अभियान के तहत वह बिलारी के ग्राम शाहपुर में यात्रा निकाली।

# गरीबों को भी मिलनी चाहिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा

- सुप्रीम कोर्ट ने की जिंदगी को जिंदा रखने की शानदार पहल

## सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाने के फैसले पर दी सहमति

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंग प्रत्यारोपण के लिए एक गाइडलाइन बनाने पर सहमति जताई है। इससे गरीब लोगों को जीवनरक्षक सर्जरी का समान अवसर मिल सकेगा। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और याचिकाकर्ता से सुझाव मांगे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने सीजेआई बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच को बताया कि अंगों की उपलब्धता का एक नेशनल डेटा ग्राइडहोना चाहिए। इससे कतार में लगे संभावित मरीजों को पता चल सकेगा कि वे कहां खड़े हैं और उन्हें अंग मिलने की कितनी



संभावना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मरीजों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को अंग प्रत्यारोपण का मौका नहीं मिल पाता है। इसकी वजह यह है कि अंग प्रत्यारोपण करने वाले 90 फीसदी अस्पताल और क्लिनिक निजी क्षेत्र में हैं। ये सिर्फ अमीर और प्रभावशाली

लोगों की पहुंच में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि वे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक ऐसा अस्पताल खोलें, जहां गरीब मरीज किफायती दर पर अंग प्रत्यारोपण सर्जरी करवा सकें। उन्होंने अंग दान करने वालों में लिंगानुपात के असंतुलन पर भी चिंता जताई।

## भारत में 'मोटिवेटेड एक्सीडेंट' के कई मामले

जस्टिस चंद्रन ने कहा कि दक्षिण भारत में मोटिवेटेड एक्सीडेंट के कई मामले सामने आए हैं। इन दुर्घटनाओं को इसलिए अंजाम दिया जाता है ताकि किसी इच्छुक मरीज को अंग मिल सके। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि यह ज्यादातर हाईवे पर होता है। केरल में इस मुद्दे पर एक फिल्म भी बनी थी, जिसकी पटकथा एक पुलिस अधिकारी ने लिखी थी, जो शायद इस घोटाले के बारे में जानता था। मेहता ने इन घटनाओं को हत्या के चौकाने वाले मामले बताया। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक और वकील परमेश्वर से कहा कि वे बुधवार को अदालत में पेश करने के लिए आदेश में शामिल किए जाने वाले सामान्य बिंदुओं का मसौदा तैयार करें। यह गाइडलाइन इसलिए बनाई जा रही है ताकि गरीब और पिछड़े लोगों को भी अंग प्रत्यारोपण का समान अवसर मिले। अभी ज्यादातर निजी अस्पतालों में ही ये सर्जरी होती है, जो महंगी होती है।

## राज्यपाल ने आसियान समिति से कहा मध्यप्रदेश के साथ साझी विकास यात्रा की अपार संभावनाएं

# मध्यप्रदेश में स्थिर, सुरक्षित और उद्योग अनुकूल वातावरण : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने आसियान समिति से कहा है कि मध्यप्रदेश के साथ साझी विकास यात्रा की अपार संभावनाएं हैं। भारत और आसियान देश साझी सभ्यता वाले क्षेत्र हैं। मध्यप्रदेश और आसियान देशों के बीच सांस्कृतिक आत्मीयता, व्यापारिक समानता और सहयोग की संभावनाएं अत्यंत मजबूत हैं। दोनों क्षेत्रों के पास युवा जनसंख्या की ऊर्जा, नवाचार की क्षमता, विविध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति तथा विकास के प्रति समान संवेदनशील दृष्टिकोण मौजूद है। प्रदेश के साथ व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में असाधारण और दीर्घकालिक साझेदारियाँ करने की अनंत संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में स्थिर, सुरक्षित और उद्योग अनुकूल वातावरण इस यात्रा को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा।

राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में आमंत्रित आसियान समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बुधवार को चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के

## आसियान समिति का प्रतिनिधि मंडल राजभवन में मिला



प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि भारत सरकार की एकट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। यह नीति भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साझा इतिहास, सांस्कृतिक जड़ों और भविष्य की समृद्ध साझेदारी को मजबूत करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के साथ

व्यापारिक, निवेश, तकनीकी, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों में निरंतर वृद्धि से पारस्परिक रिश्ते मजबूत होंगे। नए अवसर उत्पन्न होंगे। हमारी सहभागिता आने वाले वर्षों में एक नए अधिक विकसित युग का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शी नीतियों के साथ निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी वर्ष प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा 18 नवीन इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ लॉन्च की गईं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्यप्रदेश देश के उत्कृष्ट सुधारक राज्यों में शामिल है। मध्यप्रदेश की जनता सरलता, परिश्रम, सहिष्णुता और सौहार्द की मिसाल है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य की धड़कनें भारत की संस्कृति, परंपराएँ, प्रकृति, अध्यात्म, सामाजिक विविधता, आर्थिक क्षमता और आधुनिक विकास को समेटे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के नगरों, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के विकास और पर्यावरणीय संतुलन को रेखांकित किया। बताया कि राज्य में 11 औप क्लाइमेटिक जोन होने के कारण इसे देश की फूड बास्केट कहते हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने आसियान समिति नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को सांची की प्रतिकृति, स्मृति चिह्न के रूप में भेंट की। आसियान नई दिल्ली समिति के अध्यक्ष भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त श्री दातो मुजप्फर शाह मुस्तफा ने मध्यप्रदेश में प्रतिनिधि मंडल के गरिमामय स्वागत सत्कार के लिए आभार ज्ञापित किया।

- प्रधानमंत्री मोदी पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में हुए शामिल

## कार्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम के पैर छुए, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे

अमरावती (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्रप्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा- श्री सत्य साई बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान है। आगे पीएम ने कहा कि आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100 रुपए



का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले मोदी सत्य साई बाबा का मंदिर और समाधि पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा-पाठ की। जन्म शताब्दी

इवेंट में सीएम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिटी सीएम पवन कल्याण, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे।

- मोदी बोले- सत्य साई बाबा का संदेश लोगों में दिखता है- पीएम मोदी ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा का संदेश केवल पुस्तकों, प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आगे कहा कि आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक, संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अदभुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानवसेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों के सबसे बड़ा आदर्श है।

# जर्मनी का हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम अब सिर्फ भारत में बनेगा

## भारत और जर्मनी ने एक बहुत बड़ी रक्षा उत्पादन कर ली डील



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और जर्मनी ने बुधवार को दुबई एयरशो 2025 में एक हेलीकॉप्टर ऑक्सटेकल अवॉयडेंस सिस्टम (ओएएस) बनाने के लिए साझा कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत की ओर से इसकी अगुवाई हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और जर्मनी की आशिक रूप से सरकारी स्वामित्व वाली हेन्सोल्ट करेगी। इसके साथ ही भारत-जर्मनी के बीच रक्षा निर्माण के क्षेत्र में यह करीब तीन दशकों के बाद सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में ऑक्सटेकल अवॉयडेंस सिस्टम (ओएएस) बनाने का काम एचएएल के प्लांट में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की

पुण्यतिथि 8 दिसंबर से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक अगर जनरल रावत के हेलीकॉप्टर में इस तरह का सेफ्टी सिस्टम लगा होता तो शायद खराब मौसम में भी वह सुरक्षित लैंड कर सकता था। जर्मनी की कंपनी हेन्सोल्ट अब अपने ओएएस का निर्माण सिर्फ भारत के माध्यम से ही करेगी और जर्मनी में इसका उत्पादन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। पहले इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा, फिर एडवॉंस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में फिट होगा। बाद में अन्य प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल होगा। यह बिल्ड टू स्पेक मॉडल पर साझा तौर पर बनाया जाएगा। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन पर बात हुई है।

हेलीकॉप्टर ऑक्सटेकल अवॉयडेंस सिस्टम की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत लद्दाख, सियाचिन, नॉर्थ-ईस्ट, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों में है। हेन्सोल्ट में जर्मन फेडरल सरकार की 25.1% हिस्सेदारी है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन में भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक साझेदार है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस सिस्टम के निर्माण के लिए यूपी स्थित इसके कोरबा डिविजन को चुना है। यह हेलीकॉप्टर ऑक्सटेकल अवॉयडेंस सिस्टम 1,000 मीटर से भी ज्यादा दूर की बाधाओं का पता लगाने में सक्षम है। पतले से पतले तार, केबल, पोल, टावर या भौगोलिक क्षेत्र का भी यह पता लगा लेता है। तारों के समांतर उड़ते समय भी यह उसे देख लेता है, जहां कई बार रडार भी फेल हो जाते हैं।

## ऑक्सटेकल अवॉयडेंस सिस्टम की जरूरत



### तीन हमलावर नाबालिग पकड़े गए

इंदौर। तिलक नगर इलाके में स्कैप कारोबारी गौरव पर हुए हमले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह की टीम ने घटना में शामिल तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी नाबालिग को गौरव और उसकी मां की आपसी दोस्ती पसंद नहीं थी। इसी नाराजगी में उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर व्यापारी पर हमला करने की योजना बनाई। घटना तीन दिन पहले की है, जब आरोपियों ने रस्ते में अकेला देखते ही गौरव पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले के दौरान जब आसपास के लोग बचाव के लिए आए तो तीनों आरोपी वहां से भाग निकले। बाद में वे अपने-अपने घर न जाकर दोस्तों के यहां जाकर सो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज की और उन्हें मंगलवार को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी व्यापारी की हत्या करना चाहता था। फिलहाल तीनों नाबालिगों पर चाकूबाजी व अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

### सराफा चौपाटी में दो व्यापारी आपस में भिड़े

इंदौर। शहर की मशहूर सराफा चौपाटी पर सोमवार देर रात हंगामा हो गया। ग्राहक को अपनी दुकान पर लाने की बात पर दो छोटे सराफा व्यापारियों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथपाई तक पहुंच गया। सड़क पर ही दोनों ने एक-दूसरे पर थप्पड़-घूंसे चलाए और चिमटा तक चला दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोज की तरह रात में चौपाटी पर दुकानें सजी थीं। इसी दौरान ग्राहक को खींचकर अपनी दुकान पर लाने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। कुछ ही मिनटों में मामला मारपीट में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यापारियों को थाने ले गई। थाने में पहुंचने के बाद दोनों राजीनामा करने की बात करने लगे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की और दोनों को जेल भेज दिया। सराफा टीआई राजकुमार लिटोरिया के मुताबिक, छोटा सराफा इलाके के दो दुकानदार कैलाश गुर्जर निवासी जनता कॉलोनी, बड़ा गणपति और दिनेश व्यास शहर बाजार के बीच ग्राहक को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस अब दोनों के पुराने रिकॉर्ड भी चेक कर रही है।

### चार ट्रैफिक प्रहरियों का सम्मान, 11 नए शामिल

इंदौर। शहर में सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था की दिशा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ट्रैफिक प्रहरी’ अभियान को निरंतर सफलता मिल रही है। आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 1620 जिम्मेदार नागरिक ट्रैफिक प्रहरी के रूप में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में उत्कृष्ट सेवा देने वाले 4 ट्रैफिक प्रहरियों राकेश चौहान (चंदन नगर चौराहा), सुभाष निहाले (देवास नाका चौराहा), पूजा राय (राजवाड़ा क्षेत्र) तथा सुरेश दास बैरागी (गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र) को प्रशस्ति पत्र और शौल्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अभियान से हाल ही में जुड़े 11 नए ट्रैफिक प्रहरियों को पुलिस कमिश्नर ने कैप पहनाकर प्रोत्साहित किया तथा उन्हें जैकेट, सिटी, लाइट बैटन और बैज भी प्रदान किए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ‘ट्रैफिक प्रहरी’ अभियान का उद्देश्य नागरिकों को यातायात प्रबंधन की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है, ताकि शहर में बेहतर, सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नागरिक दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर गूगल फॉर्म भरकर सुविधानुसार समय और स्थान चुनकर ट्रैफिक प्रहरी के रूप में योगदान दे सकते हैं।

### पति ने नकली मंगलसूत्र पहनाया

इंदौर। महिला को पति ने झूठ बोलकर खोटा मंगलसूत्र पहना दिया। जब महिला को पता चला तो उसने आपत्ति ली। इसके बाद पीड़िता बरखा पंचोली निवासी कालिंदी गोल्ड की शिकायत पर पति राजू पंचोली के खिलाफ शिकायत की कीमत और शादी में हुए खर्च को अनुसार पति नकली मंगलसूत्र की कीमत और शादी में हुए खर्च को लेकर लगातार मांग रहा था। जब पत्नी पैसे देने से इनकार करती तो वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने बताया, मेरा पति कहता कि यदि तुम हमारी मांग पूरी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा।महिला ने आरोप लगाया है कि इस व्यवहार के चलते उसे शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। बाणगांगा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

### पुलिस को सफेद शर्ट वाले चोर की तलाश

इंदौर। होस्टलों को निशाना बनाने वाले सीरियल चोर की तलाश में पुलिस ने तेजी ला दी है। पुलिस ने होस्टल के सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर सफेद शर्ट पहने बदमाश की पहचान कर उसकी खोज शुरू कर दी है। भंवरकुआं पुलिस ने यह कार्रवाई श्री लाइब्रेरी होस्टल में रहने वाले छात्र हरू पिता वसना मेड़ा की शिकायत पर की है, जिसके मोबाइल और लैपटॉप चोरी हो गए थे। आरोपी ने शनिवार की सुबह 6 से 9 बजे के बीच होस्टल में प्रवेश किया। वह पहले छात्र के कमरे में घुसा और मोबाइल चुरा ले गया। इसके बाद आरोपी ने इसी समयावधि में होस्टल के कई अन्य कमरों में भी प्रवेश कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इन चोरियों में छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप शामिल है।

### हेलमेट पहनने की सीख दी गई

इंदौर। सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हेलमेट जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कर हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में समझाया। ऐसे वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए जिनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। नियम तोड़ने वाले चालकों का पहले चालान किया, फिर हेलमेट दिए गए। अभियान में शामिल चालकों को नियम पालन के लिए सम्मानित किया। एक चालक ने बताया कि बिना हेलमेट बाइक चलते समय उसका गंभीर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वह 13 दिन तक कोमा में रहा। इसके बाद उसने कभी भी बिना हेलमेट बाइक न चलाने का संकल्प लिया। वहीं, महिला चालक ने कहा कि हेलमेट सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

# भोपाल-पुणे बस में महिला नेशनल शूटर से छेड़छाड़, ड्राइवर-कंडक्टर नशे में

### युवती ने दोनों को जमकर पीटा, राजेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज

इंदौर। रविवार देर रात वर्मा ट्रेवल्स की भोपाल-पुणे बस में नेशनल लेवल की महिला शूटर के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय महिला शूटर जब इंदौर-पुणे रूट की बस में चढ़ रही थी, तभी कंडक्टर ने उसे बैड टच भी किया। विरोध करने पर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने बदतमीजी की, इसके बाद खिलाड़ी ने मौके पर ही दोनों की पिटाई कर दी। यह घटना भोपाल से पुणे जाते समय एक बस में हुई। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में आवेदन देकर की है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भोपाल आई हुई थीं। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह वर्मा ट्रेवल्स की बस में भोपाल से पुणे जा रही थीं। पीड़िता का आरोप है कि बस में सवार होते समय कंडक्टर ने उसके साथ बैड टच किया। कंडक्टर की हरकतों से तंग आकर महिला खिलाड़ी ने कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की जमकर पिटाई कर



दी। घटना के बाद कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही मौके से भाग खड़े हुए।

इस दौरान बस काफी देर तक सड़क के बीच में खड़ी रही। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस को रुका देखकर अन्य यात्रियों ने तुरंत बस संचालक से संपर्क किया। ऑपरेटर ने आनन-फानन में एक दूसरे ड्राइवर को मौके पर भेजा। तब कहीं जाकर बस पुणे की ओर खाना हो सकी। पीड़िता ने घटना के संबंध में राजेंद्र नगर पुलिस थाने में एक शिकायती आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच

# भूपेंद्र सुसाइड केस की आरोपी इति तिवारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट से नामंजूर

### हाईकोर्ट ने कहा ‘सुसाइड नोट देखकर फिलहाल जमानत देना उचित नहीं’

इंदौर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पब संचालक भूपेंद्र रघुवंशी की आत्महत्या मामले में आरोपी बनाई गई इति तिवारी को सोमवार को हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। इति तिवारी द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट का उल्लेख करते हुए कहा कि फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है।

मामला 30 अगस्त का है, जब भवानी नगर निवासी और तीन पब-बार के संचालक भूपेंद्र रघुवंशी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रारंभिक जांच में इति तिवारी, उसकी बहन शिवांगी और उसकी सहेली आरशा का नाम सामने आया था। हालांकि, पुलिस ने मुख्य आरोप इति तिवारी पर ही तय किया। घटना के तीसरे दिन इति ने अपने वकीलों के माध्यम से अवज्ञापूर्ण थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जमानत याचिका में इति ने अपने बचाव में यह दावा किया था कि वह एक प्रतिष्ठित ब्रांडेड कंपनी में कार्यरत है और निर्दोष है, इसलिए उसे जमानत दी जानी



चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मृतक द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट और दर्ज बयान बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभी इस स्तर पर आरोपी को रहत नहीं दी जा सकती। वहीं मृतक भूपेंद्र रघुवंशी के परिवार ने इति की जमानत का तीव्र विरोध किया था।

परिवार की ओर से हाईकोर्ट एडवोकेट योगेश कुमार गुप्ता और अभिषेक रघुवंशी ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराते हुए तर्क दिया कि भूपेंद्र ने मरने से पहले पांच पन्नों का विस्तृत

सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें इति तिवारी के नाम का स्पष्ट उल्लेख है।

नोट में भूपेंद्र ने इति की कथित प्रताड़ना, दबाव और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। परिवार ने कोर्ट को यह भी बताया कि मृतक के ड्राइवर ने भी अपने बयान में इति, शिवांगी और आरशा के नाम लिए थे। पुलिस ने मामले में मृतक के परिवारजनों और करीबी दोस्तों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें इति द्वारा मानसिक दबाव बनाने और झगड़े के कई प्रसंग सामने आए।

# इंदौर में इन 23 सड़कों पर टूटेंगे मकान व दुकानें, ट्रैफिक सुधरेगा

### नगर निगम केविएट दायर करके स्टे का रास्ता भी बंद करेगी



इंदौर। शहर के पूर्वी इलाके मालवीय नगर में नगर निगम ने 140 मकानों को तोड़ा। अब शहर की 23 सड़कों पर भी ऐसे ही मकानों को तोड़ा जाएगा। शहर में बढ़ रही गाड़ियों और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए शहर के पुराने रहवासी क्षेत्रों के घरों, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए नगर निगम हाई कोर्ट में केविएट भी दायर कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद यहां रहने वाले रहवासियों को कोर्ट से भी स्टे नहीं मिलेगा। इन 23 सड़कों पर तोड़फोड़ होगी- जिसी चौराहा से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक (24 मीटर), नेमोनाथ चौराहा से जिसी चौराहा तक (24 मीटर), सुभाष मार्ग गोल मंदिर से रामबाग पुल तक (30 मीटर), मच्छी बाजार चौराहा से चंद्रभागा पुल तक (24 मीटर), टीसीएस से एमआर-5 तक लिंक रोड (30 मीटर), एमआर-10 से एमआर-12 को जोड़ने वाली लिंक रोड (30 मीटर), एयरपोर्ट रोड से एमआर-5 को जोड़ने वाली लिंक रोड (30 मीटर), एमआर-5 बड़ा बांगइदा से पीएमएवाय मल्टी तक (30 मीटर), भमोरी चौराहा से एमआर-10 और राजशाही गार्डन से होटल वाव तक (30 मीटर), सांवेर डेप्टेल पंप से

# ढाई साल की अनिका को चाहिए 9 करोड़ रु का जीवनरक्षक इंजेक्शन

### माता-पिता ने जनसुनवाई में भी मदद के लिए गुहार लगाई

इंदौर। राजगढ़ के ब्यावरा में ट्रेवल्स कंपनी में काम करने वाले प्रवीण शर्मा इन दिनों अपनी ढाई साल की बेटी अनिका के इलाज के लिए इंदौर में प्रयास कर रहे हैं। अनिका एसएमए टाइप-2 (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) से जूझ रही है। यह ऐसी दुर्लभ बीमारी जो दस लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी के कारण इलाज में देरी होने पर बच्चा जीवनभर के लिए अपंग हो सकता है। इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र प्रभावी उपचार अमेरिका में बनाया गया 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, जिसे अगले दो महीनों के भीतर लगाना बेहद जरूरी है। अपनी बेटी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की उम्मीद में अनिका के माता-पिता आज मंगलवार की जनसुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा के पास पहुंचे हैं। भावुक होते हुए मदद की गुहार लगाईं। माता-पिता ने बताया कि अनिका एसएमएस टाइप-2 (स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी) नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में बच्चों की मांसपेशियाँ धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं। अनिका का वजन भी लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उसका उपचार चल रहा



है, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि लगभग 9 करोड़ रुपए कीमत वाला विशेष इंजेक्शन ही उपचार का मुख्य विकल्प है, जिससे बच्चे की जान बचाई जा सकती है। मध्यमवर्गीय परिवार के माता-पिता के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना असंभव है। इसलिए वे शासन और समाज से सहायता की अपील कर रहे हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने उनकी बात गंभीरता से सुनकर सकारात्मक आश्वासन दिया तथा मीडिया व समाज के माध्यम से बच्ची की मदद के लिए आगे आने की अपील की। अनिका की मां सारिका, जो इंदौर की ही रहने वाली हैं, महीनों से बेटी को बचाने के लिए मदद की हर संभावना पर दस्तक दे रही हैं। राजगढ़ में केवल 20 लाख रुपए ही जुट पाए, जिसके बाद परिवार इंदौर पहुंचा। यहां कई जनप्रतिनिधि आगे आए।

# पुलिस जनसुनवाई में मध्यस्थता केंद्र की मदद से लेन-देन का केस निपटा

इंदौर। पलासिया स्थित कंट्रोल रूम में आयोजित जनसुनवाई में 47 शिकायतें आईं। सभी शिकायतों को सुनकर पुलिस आयुक्त ने उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया। इसी क्रम में दो महत्वपूर्ण मामलों के सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। जनसुनवाई में पहली बार इस तरह का मामला सामने आया। इसमें पुलिस ने केस दर्ज न करते हुए आपसी बातचीत से सुलह कराई।

66 वर्षीय सतीश कुमार शर्मा निवासी सेक्टर श्री ऋषि पैलेस थाना द्वारकापुरी ने

### दो महत्वपूर्ण मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया

शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल का ऋण एलएंडटी फाइनेंस कंपनी से कराया था।

इस प्रक्रिया में कंपनी के कर्मचारी संतोष जाट को उन्होंने 30,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे, परन्तु यह राशि कंपनी में जमा नहीं की गई। जनसुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से बुलाया गया। समझाइश के बाद अनावेदक ने तत्काल आवेदक को 30,000 नगद वापस कर दिए।

दूसरे प्रकरण 44 वर्षीय अतुल श्रीवास्तव निवासी विलफर्टन पार्क, कनौटखेड़ी थाना लसूडिया की शिकायत पर कार्रवाई की गई। प्रकरण क्रमांक 585/25 में 17 नवंबर को अनावेदक गगन कलसी पिता राजेंद्र सिंह कलसी से मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से आवेदक को 44 ग्राम सोना और 2,00,000 नकद, कुल लगभग 6,00,000 रुपए वापस दिलाए। इस मामले का भी समाधान मध्यस्थता केंद्र से हुआ।

# उत्कृष्ट कार्य करने पर 18 पुलिसकर्मी सम्मानित, पुलिस कमिश्नर ने दिए पत्र

इंदौर। पुलिस कमिश्नरेट में नागरिकों के लिए बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 18 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में आजाद नगर थाने की उपनिरीक्षक रचना परमार को ऑपरेशन मुस्कान के तहत अपहृत को दस्तयाब करने, गांधीनगर थाने के उपनिरीक्षक सुरेंद्र मेहता को गुमशुदगी के एक प्रकरण में, एरोड्रम थाने की उपनिरीक्षक रुपाली श्रीवास्तव को गुमशुदा नाबालिग को खोजने में, खजराना थाने के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक ब्रजेश खिंची, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक नरेश चौहान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक अजित यादव, आरक्षक एजल सिंह गुर्जर तथा आरक्षक प्रदीप सूर्यवंशी को अंधे कत्ल का

पदाफांश करने सम्मानित किया गया।

इसी तरह थाना सेन्ट्रल कोतवाली के सहायक उपनिरीक्षक जगन्नाथ सिंह, प्रधान आरक्षक सूबेदार सिंह को वाहन चैकिंग के दौरान वाहन चोरी का खुलासा करने, द्वारकापुरी थाने के आरक्षक अनुराग सिंह, कृष्णचंद्र शर्मा, अरुण माथुर तथा गौरव परमार को 325 ग्राम सोने की ठगी का मामला सुलझाने, आसूचना विभाग के प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा को थाना हीरानगर के अंधे कत्ल के फरार आरोपी को पकड़ने, अपराध शाखा के उपनिरीक्षक अमित कटियार को 25.39 ग्राम एमडी ड्रग्स जप्त करने, कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक मंगलेश्वर बघेल को आर्म्स एक्ट के मामले में 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ने, आरक्षक मुकेश यादव को 55.85 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जप्त करने पर पुरस्कार के लिए चुना गया है।



संपादकीय

शेख हसीना-प्रायोजित मृत्यु दंड

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहराकर सजा ए मौत सुनाई है। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ भड़के छत्र विद्रोह में पुलिस व सेना की कार्रवाई में 1400 लोग मारे गए थे। इसका दोष वहां की अंतरिम मोहम्मद युनुस सरकार ने शेख हसीना पर मढ़ते हुए उन्हें सजा देने के लिए भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि भारत इसे मानेगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि शेख हसीना भारत की पकड़ी दोस्त रही हैं और भारत अपने मित्रों को कभी धोखा नहीं देता। शेख हसीना को जिस तरह मौत की सजा सुनाई गई है, उसकी आशंका पहले से ही थी। क्योंकि यह प्रायोजित और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ चलाया गया मुकदमा था। इसमें शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। इक तरफ सबूतों और गवाहियों के आधार पर मृत्यु दंड सुना दिया गया। फैसले के मुताबिक हसीना को 30 दिन के भीतर सरेंडर करना होगा। साथ ही उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। फैसले में अवामी लीग के वस नेता को हिंसक दमन का 'मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार' बताया गया। खुद शेख हसीना ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने भी इस फैसले को अमान्य कर दिया है। खास बात यह है कि शेख हसीना को सजा सुनाने वाली अदालत खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण कहती है, जिसकी स्थापना 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुई थी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी मामले की निष्पक्ष सुनवाई की बात कही थी। वैसे भी अब यह साफ हो चुका है कि शेख हसीना के खिलाफ जो कथित छत्र आंदोलन खड़ा किया गया था, वह कट्टरपंथियों द्वारा हसीना को हटाने की छुपी चाल थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत बांग्लादेश की हसीना के प्रत्यर्पण की बात मानेगा? इसकी संभावना न्यूनतम है। शेख हसीना के पास बांग्लादेश की कोर्ट में 17 दिसंबर 2025 तक सरेंडर कर अपील करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है। हसीना फैसले के खिलाफ तब तक अपील नहीं कर सकती जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं कर देती या गिरफ्तार नहीं हो जाती। यानी उनके पास इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश के इस फैसले को चुनौती देने के लिए 17 दिसंबर 2025 तक का ही वक्त है। यदि शेख हसीना इस तारीख तक बांग्लादेश की किसी कोर्ट में सरेंडर नहीं करतीं या गिरफ्तारी नहीं देती हैं, तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। उनके पास दूसरा विकल्प यह है कि वो भारत में ही रहें और भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो उन्हें किसी हाल में बांग्लादेश को न सौंपे। असदुज्जमां खान भी भारत में ही हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन इसमें कुछ पतली गलियाँ भी हैं, जिनके आधार पर भारत सरकार हसीना को सौंपने से इंकार कर सकती है। उधर बांग्लादेश में इस फैसले का व्यापक विरोध हो रहा है। युनुस सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुल मिलाकर हालात और खराब होने का अंदेशा है। परिस्थितियां गृह युद्ध भड़कने की ओर इशारा कर रही हैं। भारत को भी सतर्क रहना होगा।

नजरिया

अजित लाड

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक



बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आधिकारिक नतीजों ने एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया। इस बार एग्जिट पोल्स ने लगभग वही रूझान दिखाए, जो अंततः मतगणना में सामने आया। यह वही बिहार है, जहां 2015 के चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल बुरी तरह चूक गए थे और 2020 में भी कई अनुमानों ने विचलन दिखाया था। लेकिन, 2025 के चुनाव ने यह भरोसा मजबूत किया कि यदि सैंपलिंग वैज्ञानिक, बूथ चयन सटीक और जनसांख्यिकीय विश्लेषण गहरा हो, तो एग्जिट पोल महज अनुमान नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय शोध-संकेतक बन सकते हैं। सबसे पहले बात कामख्या एनालिटिक्स की। इस एजेंसी ने एनडीए के लिए 167-187 सीटों की रेंज दी थी और अंतिम नतीजे जब इसी के आसपास उठर गए। इससे साफ हो गया कि इसकी सैंपलिंग रणनीति सबसे अधिक सटीक साबित हुई। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय-सामाजिक जटिलताएं बहुत गहरी हैं, इस स्तर की भविष्यवाणी आसान नहीं होती। इसका अर्थ है कि कामाख्या ने बूथ चयन, जातिगत वेटेज और क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन इतनी बारीकी से किया कि जमीनी संकेत सही पैमाने में कैप्चर हो गए।

मेट्राइज़ (147-167) और टुडेज चाणक्य (148-172) ने भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत में दिखाया था और वास्तविक नतीजों ने उनके अनुमानों को लगभग पूरी तरह सही साबित किया। विशेषकर चाणक्य की मॉडलिंग जो पिछले कुछ वर्षों में अपनी उच्च सटीकता के लिए पहचानी जाती है, एक बार फिर भरोसेमंद निकली। महागठबंधन के लिए कामाख्या (54-74), मेट्राइज़ (70-90) और चाणक्य (65-89) द्वारा दी गई रेंज भी परिणामों से काफी मेल खाती रही। जो बताती है कि इन एजेंसियों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ताकत का संतुलित आकलन किया था। छोटे दलों की भविष्यवाणी करना आमतौर पर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनका वोट बिखरा हुआ होता है और उनका प्रभाव

एग्जिट पोल- डेटा, धारणा और लोकतंत्र का वैज्ञानिक चेहरा

बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव एक बड़ी सीख देता है। लोकतंत्र सिर्फ राजनीति की समझ पर नहीं चलता, बल्कि यह डेटा, सांख्यिकी, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धतियों पर भी आधारित है। एग्जिट पोल कोई जादू नहीं हैं; वह तो हजारों वोटर्तों के व्यवहार, सामाजिक पैटर्न, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और सांख्यिकीय विश्लेषण का संयुक्त परिणाम होते हैं। वे 100 फीसदी शुद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि, समाज और मनुष्य दोनों गतिशील हैं।

क्षेत्र-विशेष तक सीमित रहता है। लेकिन, इस बार यहीं भी सटीकता उल्लेखनीय रही। उदाहरण के तौर पर मेट्राइज़ ने जेएसपी/जेएसयूपी को ठीक 5 सीटें दीं। जबकि, एक्सिस माय इंडिया ने 0-2 सीटों की संभावना जताई थी और चुनाव परिणाम इन्हीं अनुमानों के आस-पास रहे। पीपुल्स पल्स ने एनडीए के लिए 133-159 और महागठबंधन के लिए 75-101 का व्यापक रेंज दिया था, फिर भी उसका आकलन

एक ही दिशा में था एनडीए की बढ़त। जब अलग-अलग स्थानों पर काम कर रही टीमें, अलग-अलग मॉडलिंग पद्धतियों, सैंपलिंग फ्रेम्स और डेटा-संग्रह तकनीकों के बावजूद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, तो यह किसी भी चुनाव विश्लेषण के लिए 'डेटा-संगति' का मजबूत प्रमाण होता है। इस बार लगभग सभी प्रमुख एजेंसियों ने बूथ कवरेज का विस्तार किया, डेमोग्राफिक मैपिंग को सूक्ष्म रखा,

का परिणाम है कि अधिकांश एग्जिट पोल असली नतीजों के बेहद करीब उतर आए। चुनावी परिणामों के बाद एक और तथ्य सामने आया कुछ राजनीतिक हलकों में जिस 'फेक एग्जिट पोल' का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, वह इस बार पूरी तरह धराशायी हो गया। सामूहिक सटीकता इतनी प्रबल थी कि किसी भी तरह के आरोप स्वतः ही निरर्थक साबित हो गए। जनता ने भी देखा कि इस बार एग्जिट पोल न वास्तविकता से दूर थे, न किसी एकतरफ़ा झुकाव वाले प्रतीत हुए। 2025 का यह चुनाव एक बड़ी सीख छोड़ता है। लोकतंत्र सिर्फ राजनीति की समझ पर नहीं चलता, बल्कि डेटा, सांख्यिकी, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धतियों पर भी आधारित है। एग्जिट पोल कोई जादू नहीं हैं; वे हजारों वोटर्तों के व्यवहार, सामाजिक पैटर्न, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और सांख्यिकीय विश्लेषण का संयुक्त परिणाम होते हैं। वे 100 फीसदी शुद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि, समाज और मनुष्य दोनों गतिशील हैं। यदि सर्वेक्षण ईमानदार हों, सैंपलिंग वैज्ञानिक हो और डेटा वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता हो, तो एग्जिट पोल जरूर चुनावी माहौल का विश्वसनीय संकेतक बनते हैं। बिहार चुनाव 2025 ने इस तथ्य को सबसे सशक्त रूप में सिद्ध किया है। यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि चुनाव-अध्ययन और डेटा-विश्लेषण को दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। यह संदेश स्पष्ट है वैज्ञानिक दृष्टि, पारदर्शी डेटा और सटीक मॉडलिंग लोकतंत्र को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाती है। एग्जिट पोल इस बार सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समझ का एक वैज्ञानिक दर्पण बनकर उभरे हैं और यह निस्संदेह एक सुखद और प्रेरक संकेत है।



अंतिम ट्रेंड की दिशा के बिल्कुल अनुरूप रहा। इसी तरह भास्कर एग्जिट पोल (145-160 / 73-91) भी बिना किसी बड़े विचलन के, राजनीतिक हवा को पढ़ने में सफल रहा। अन्य एजेंसियां जैसे पी-माक, पोल स्टार्ट और पीपुल्स इनसाइट ने भले ही अपेक्षाकृत व्यापक रेंज दी हो, लेकिन इन सभी का सामूहिक संकेत

वोटर प्रोफाइलिंग को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया और सैंपलिंग विधि को पिछले चुनावों की तुलना में कहीं अधिक परिशुद्ध बनाया। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ लगातार बदलती रहती हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी

जलवायु सम्मेलन

कुमार सिद्धार्थ

लेखक पिछले चार दशक से पत्रकारिता और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं।



दुनिया के सबसे विशाल वर्षावन अमेज़न पर खतरा अब किसी दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक निकट आती सच्चाई है। वनों की अंधाधुंध कटाई, तेल और गैस के उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तन ने इसे उस बिंदु तक पहुँचा दिया है जहाँ से लौटना शायद संभव नहीं रहेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अमेज़न अब 'कार्बन सोखने वाले' वन से 'कार्बन छोड़ने वाले' क्षेत्र में बदलने की कगार पर है। ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन सीओपी-30 ब्राज़ील के बेलें शहर में चल रहा है, एक नई रिपोर्ट ने उस वित्तीय ढाँचे को बेनकाब किया है जो अमेज़न के विनाश की जड़ों में छिपा है। पर्यावरण संगठन स्टैंड.अर्थ की रिपोर्ट 'बैंक्स वर्सेस द अमेज़न स्कोरकार्ड' बताती है कि 2016 में पेरिस समझौते के बाद से अमेज़न क्षेत्र में तेल और गैस परियोजनाओं को मिलने वाले वित्त का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा सिर्फ दस बैंकों से आता रहा है। इनमें जेपी मॉर्गन चेज, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, इटाउ यूनिबैंको (ब्राज़ील) और एचएसबीसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन बैंकों ने अमेज़न के भीतर जीवाश्म ईंधन से जुड़ी परियोजनाओं में 15 अरब डॉलर से अधिक झोंक दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूरोप के कई बैंकों ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। फ्रांस का बीएनपी पारिबा और ब्रिटेन का एचएसबीसी अब अमेज़न से जुड़ी कंपनियों को ऋण देना बंद कर चुके हैं। उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं जो अमेज़न में तेल और गैस उत्खनन करने वाली कंपनियों को वित्त नहीं देती। लेकिन जहाँ यूरोपीय बैंक पीछे हटे, वहीं अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बैंक उस खाली जगह को भरने में लगे हैं। ब्राज़ील का इताउ यूनिबैंको अब शीर्ष पर पहुँच गया है — सिर्फ पिछले 18 महीनों में उसने 378 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग दी है। जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका उससे थोड़ा पीछे हैं। इसी समय में पेरु के क्रेडिकॉर्प और कनाडा के स्कोटियाबैंक ने भी अपने निवेश को लगभग तीन गुना बढ़ा दिया है।रिपोर्ट की प्रमुख शोधकर्ता डॉ.

अमेज़न को कौन कर रहा है बर्बाद?

देवयानी सिंह का कहना है कि यूरोपीय बैंकों ने अपेक्षाकृत सबूत नीतियाँ लागू की हैं, लेकिन कोई भी बैंक अब तक अपने वित्तपोषण को शुन्य नहीं कर पाया। हर बैंक को लूप होल बंद करने होंगे और बिना देरी अमेज़न से बाहर निकलना होगा। द इकोलॉजिस्ट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, अमेज़न में तेल और गैस की खुदाई सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया में 6,000 से अधिक तेल-दूषित स्थल दर्ज किए गए हैं। उत्खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों में कैंसर, गर्भपात और श्वसन रोगों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद, सरकारें पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्राज़ील ने इस साल की शुरुआत में 68 नए तेल ब्लॉक की नीलामी की। इक्वाडोर में यासुनी नेशनल पार्क में ड्रिलिंग रोकने के लिए 2023 में हुए जनमत-संग्रह के बाद भी काम जारी है। पेरू में 31 नए तेल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से कई 400 से अधिक स्वदेशी समुदायों की भूमि से ओवरलैप करते हैं। अमेज़न की ओलिविया बिंसा कहती हैं, जब जंगल खुद संकट में है, तब बैंक ऑफ अमेरिका, स्कोटियाबैंक और इताउ जैसे बैंक इन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। दशकों से हमारे समुदाय इस विनाश का सबसे बड़ा भार उठा रहे हैं। अब समय आ गया है कि बैंक अमेज़न को तेल की लत से मुक्त करें। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 से अब तक अमेज़न क्षेत्र में 2 अरब डॉलर से अधिक की नई फंडिंग केवल छह कंपनियों को मिली है- पेद्रोब्रास, एनेवा, गनवोर, ग्रैन टिएरा, वलस्पेट्रोल कैमिसेआ और हंट ऑयल पेरू। इन सभी पर भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय क्षति और स्वदेशी अधिकारों के उल्लंघन के आरोप हैं। ब्राज़ील की कंपनी एनेवा को हाल ही में संघीय अदालत ने अपनी गतिविधियाँ रोकने का आदेश दिया था क्योंकि उसने

स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया था। फिर भी, उसे इताउ यूनिबैंको, बैंकों डो ब्रासिल, सैंटेंडर और अन्य बैंकों से वित्त मिलता रहा। इसी तरह, स्विस् कंपनी गनवोर को 2013 से 2020 के बीच इक्वाडोर में अधिकारियों को रिश्त देकर तेल अनुबंध हासिल करने का दोषी पाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसे आईएनजी बैंक से वित्तीय सहायता मिलती रही। इससे यह साफ़ होता है कि आंशिक प्रतिबंध और 'प्रोजेक्ट-लेवल' नीतियाँ अक्सर औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं होतीं। रिपोर्ट में सभी बैंकों से अपील की गई है कि वे 2030 तक अमेज़न में तेल और गैस परियोजनाओं के वित्तपोषण को पूरी तरह समाप्त करें - चाहे वह ऋण के रूप में हो, बॉन्ड में निवेश के रूप में या परामर्श सेवाओं के रूप में। साथ ही, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की स्वदेशी अधिकारों पर घोषणा (NDRIP) के अनुरूप नीतियाँ अपनाने की सिफारिश की गई है। स्टैंड.अर्थ की वरिष्ठ अभियानकर्ता मार्टीना डोमिनियाक कहती हैं, कॉप-30 सम्मेलन बैंकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि वे अमेज़न में जीवाश्म ईंधनों के वित्तपोषण को बंद करने की ठोस घोषणा करें। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार का सवाल है। आज अमेज़न वह सॉस है जिससे पृथ्वी जीवित है। पर यदि यह सॉस रुक गई, तो इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ेगा। आने वाला दशक तय करेगा कि यह महान वन जीवित रहेगा या इतिहास बन जाएगा। कॉप-30 सम्मेलन के दौरान यह सवाल सिर्फ सरकारों या पर्यावरणविदों के लिए नहीं, बल्कि उन बैंकों के लिए भी है जिनके धन से यह विनाश चल रहा है। अगर उन्होंने दिशा बदली, तो बेलें में चल रहा यह सम्मेलन अमेज़न को बचाने की नई शुरुआत कर सकता है। और अगर नहीं, तो यह सभ्यता की सबसे हरी विरासत को खो देने की औपचारिक घोषणा होगी।

बिहार की औरतों को क्यों दोष दिया जा रहा?

विधानसभा चुनाव 2025

डॉ. तेजी ईशा

लेखक एसजीटी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग में कार्यरत हैं।



बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया। रिजल्ट में एनडीए को बहुमत मिला, फिर से नीतीश सरकार के बनने का रास्ता साफ हुआ। ये फैसला बिहार की जनता का था। स्त्री-पुरुष दोनों मतदाताओं का था। अगर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम देखेंगे तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष कहीं टिका ही नहीं। एक तरफा चुनाव था, ये परिणाम से साफ हुआ। लेकिन इस बार महिला मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर वोट किया। बिहार में महिला मतदाताओं के वोट प्रतिशत आज ही नहीं बढ़े हैं। वर्ष 2005 के बाद से हर चुनाव में महिलाओं में वोटिंग में आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। इस मामले में कोरोना काल में हुए चुनाव अपवाद हो सकते हैं। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि ज्यादा संख्या में वोट वजह से नीतीश सरकार या एनडीए को महिलाओं का वोट मिला। जबकि ये सरासर गलत बात है। आप कह सकते हैं कि इस योजना ने महिलाओं को सरकार के पक्ष में वोट करने का एक और कारण दे दिया लेकिन केवल दस हजार रुपए मिलने की वजह से महिलाओं ने वोट किया, ये गलत है। सरासर गलत है। नीतीश कुमार जब पहली दफा राज्य के मुखिया बने तभी से उन्होंने महिला मतदाताओं को ध्यान में रख ये योजनाएं चलाई। 2008 में नीतीश कुमार ने हार्ड स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दिलाया था। देखते-देखते गाँव-देहात की फिजा बदल गई थी। स्कूली ड्रेस पहने लड़कियाँ बूढ़ में साइकिल से स्कूल जाने लगीं। जब लड़कियां बाहर निकलीं तो कुछ शोहदे उनको परेशान करने लगे। नीतीश कुमार ने बिना 'एनकाउंटर' किए

लड़कियों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कोई परेशान करेगा तो पुलिस उसका इलाज करेगी। फिर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण। बिहार पुलिस में लड़कियों के लिए आरक्षण का इंतजाम इस मुख्यमंत्री ने किया। शराब पीकर जब घर के मर्द नाटक करने लगे। घर की बेटी-पत्नी को मारने-पीटने लगे तो नीतीश ने शराबबंदी जैसा सख्त कदम उठाया। राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने वो फैसला वापिस नहीं लिया। इससे भी राज्य की महिलाओं में एक भरोसा जगा। और इन सभी वजहों से हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने नीतीश का समर्थन किया। कम या जायदा। इस चुनाव में तो एक नई पार्टी भी थी। वो पार्टी कह रही थी कि हम चुनाव जीते तो सबसे पहले शराबबंदी खत्म करेंगे। उस पार्टी और उस दल के मुखिया ने ये भी नहीं सोचा कि एक बार महिलाओं से राय ले लें। उनसे पछु लें। समझ लें। इससे उलट नीतीश कुमार ने अपने पूरे टर्म में। बीस साल के शासनकाल में महिलाओं को आगे रखा। अपने शुरुआती समय में नियमित तौर से महिलाओं की पंचायतें बिठाते थे और उसमें खुद जाते थे। वहीं घंटों बैठ के महिलाओं की बातें सुनते थे। मेरे कहने का मतलब कि नीतीश सरकार ने अपनी शुरुआती दिनों से राज्य की महिलाओं को एक अलग वोट के तौर पर देखा है। उन्होंने लड़कियों को 'जहां परिवार कहाँ वहीं वोट डालने की मशीन' नहीं माना। और इस वजह से राज्य की महिलाएँ हर चुनाव में नीतीश में अपना भरोसा जताती रहीं हैं। इसलिए ये कहना बंद कर देना चाहिए कि महिलाओं ने कुछ पैसे के लातच में अपना वोट बेच दिया। उन्होंने नीतीश को वोट दिया क्योंकि नीतीश ने उन्हें पुरुषों से अलग समझा। उनकी आवाज। उनकी जरूरतों को समझा। उसके मुताबिक सरकार के नियम बनाए। सरकारी योजनाओं में महिलाओं को उनका हिस्सा दिलावाया। और अगर एक मिन्ट के लिए मान भी लिया जाए कि महिलाएँ दस हजार के चक्र में बिक गईं तो राज्य के पुरुष तो सालों से शराब और एक समय के खाने के लिए बिकते रहे हैं। तब तो कोई पुरुषों को निशाना नहीं बनाता फिरता था। एक बार आखिर में कह दूँ, अगर राज्य के नेता और विपक्षी पार्टियां ये मान के आज बैठ गईं कि नीतीश सरकार को महिलाओं ने वोट केवल दस हजार रुपये के चक्र में दिया है तो यकीन मानिए, आज से पाँच साल बाद होने वाले वाला चुनाव भी वो हार चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव में उनकी हार के असल वजह वो खोज ही नहीं पाए। और अगर सही वजह ही नहीं खोज पाए तो उसे ठीक क्या खाक करेंगे!

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए अमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बाँबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/2010/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।



इधर साहित्य के इलाके में बादल बहुत घुमड़ रहे हैं। दिन दिन भर अंधेरा छाया रहता है, रात रात भर चांद-तारे गायब रहते हैं। जितने भी लोग बादल देखते हैं उनमें से आधे दम से कवि हो जाते हैं। बचे हुए में से आधे लघुकथाकार और बाकी से व्यंग्यकार, कथाकार, निबंधकार वगैरह पैदा होते हैं। उम्मीद तो रहती है कि बादल से पानी बरसेगा लेकिन टपकते हैं साहित्यकार और कुछ परजीवीनुमा भी आ जाते हैं मैदान में। अब आए हैं तो गीला भी होगा, कुछ कीचड़ भी और कुछ नाले -नदी, तालाब में भी पहुंचेंगे। भाई पानी तो पानी है, जिधर ढलान मिलेगी वह चल पड़ेगा। इसमें कोई रोक तो है नहीं। इस झरते बरसते मौसम में साहित्य की सेवा यदि

गोपीचंद बाँडी सप्लायर

कोई कर रहा है तो वह प्रकाशक है। आप साहेबान दनादन लिखिए हम धड़धड़ छापेंगे। बस हो गया काम, आपका भी और हमारा भी। क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है, पाठक क्या होता है, क्या चाहता है इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल कोई कमबख्त करे तो उसे मौका मिलते ही सूखे कुवें में डाल दो। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो भुगताना ही पड़ता है। पाठक लोग कोई दूसरी दुनिया के नहीं हैं। साहित्य सेवा के लिए प्रकाशक बेचारे को खूब सारे गीले-सूखे शब्द चाहिए जिन्हें वह किताब में बदल सकें। लेखक और प्रकाशक राजस्थानी समथी की तरह होते हैं। खूब गले मिलते हैं लेकिन रियायत जरा भी नहीं करते हैं। मजे की बात यह है कि यह गलाकट रिस्ता एक बार बनता है तो जीवन भर के लिए बन जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। याद

दिला दें कि पुस्तक प्रकाशन के बाद भी पाठक की किसी को याद नहीं आती है। अब अगर पुस्तक का विमोचन नहीं हो तो मतलब क्या है साहित्य सेवा का!! लिखी, छपी, हाथ में आ गई, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। विमोचन के अलावा और किया भी क्या जा सकता है। किसी आयोगन वैज्ञानिक को साथ में ले लो तो सब काम आसान हो जाता है। मतलब अतिथि, मुख्य अतिथि वगैरह वही फिट करवा देता है।

हाँल, फोटोग्राफर, प्रेस रिपोर्टर और खाने-पीने का बढ़िया इंतजाम आपकी जेब को ही करना है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आयोजन में लोगों की उपस्थिति को लेकर। लोग आते नहीं हैं आजकल, जाहिल कहीं के। चाय-समोसा खिलाओ तो भी हाँल बन पर पाता है। लेखक को मजबूरन गोपीचंद बाँडी सप्लायर के पास जाना पड़ता है।

गोपीचंद हर मौके के लिए 'बाँडी' सप्लायर करता है। चाहे शादी हो, बारात, उठावना या पुस्तक विमोचन। वह सजी-धजी, धोई-धुलाई बाँडीज भेजता है। पॉलिश किए जूते, इस्तीरादार कपड़े और चेहरे पर साहित्यिक गहराई का भाव अलग से। विमोचन कार्यक्रम थोड़ा बोरिंग होता है, इसलिए बीच-बीच में तालियाँ भी बजानी पड़ती हैं, मौके बेमौके वाह वाह भी करना पड़ती है। यही कारण है कि इस प्रजाति की बाँडी थोड़ी महींगी मिलती है। लेकिन भैया, जब साहित्य में सिर दे ही दिया है तो सस्ता महंगा क्या देखना! अगले दिन अखबार में इस खबर के साथ फोटो छपेगी - 'लेखक महोदय का गरिमामय विमोचन समारोह संपन्न'। तो फटाक से फेमस भी तो हो जाओगे। किताबों को तो कहीं जाना नहीं है, अपने घर में ही पड़ी रहेंगी। तो भाई लोगों आगे-पीछे मत देखो.... चले चलो, बढ़े चलो।













## इटारसी में स्मार्ट फिश पार्लर का संचालन नगर पालिका शुरू करवाए कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में दिए निर्देश

**नर्मदापुरम (निप्र)।** नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने संभागीय समय सीमा की बैठक में उपसंचालक कृषि श्री जे आर हेड्राऊ को निर्देश दिए कि वह सप्ताह में 1 दिन जिले में किसी भी स्थान पर जैविक हाट बाजार लगाना सुनिश्चित करें। जैविक हाट बाजार में जैविक सामग्री,जैविक खाद एवं औषधि की मार्केटिंग की जाए। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन को निर्देश दिए कि वह इटारसी में बनाए गए स्मार्ट फिश पार्लर में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए उसका संचालन शुरू करवाए। कमिश्नर श्री तिवारी ने जिले में पुनः कई जगह नरवाई जलाने की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी किसानों को समझाइश दी जाए कि वह नरवाई ना जलाएं। उन्होंने एक बगिया मां के नाम के तहत दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि अमले सप्ताह उन्हें लक्ष्य पूर्ति के संबंध में जानकारी से अवगत कराया जाए। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग की कामधेनु योजना में अदयानन प्रगति लाने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि गौशालाएं बढ़ाने की दिशा में भी संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत देते हुए कहा कि सभी जिलों में केस कल्चर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है अतः बजट शासन से प्राथमिकता से मांग कर लक्ष्य की पूर्ति की जाए। कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों को जिला



चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए साथ ही उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वह जिला पोषण विकास समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करें। उन्होंने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वह आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान प्रारंभ कराए और दिए गए लक्ष्य के अनुसार सत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। 70 वर्ष से अधिक एवं सामान्य वाला कार्ड भी दिए गए लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत बनाया जाए। कमिश्नर ने गत दिसंबर माह में हुए इन्वेस्टर कॉन्फ्लेव में लिए गए निर्णय एवं वादे को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वकर्मा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण वितरण

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण की मॉनीटरिंग भी सजग रूप से की जाए। कमिश्नर ने जिला स्तरीय कौशल विकास समिति की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटीआई अधिकारी उक्त बैठक आयोजित करें। उन्होंने जगह-जगह नवाई जा रही अवैध कॉलोनी को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। और कहा कि नगर पालिका तत् संबंध में आवश्यक संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने राम पथ गमन पथ पर विकास कार्य करने के भी निर्देश दिए,और कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातिय कार्य विभाग विद्यार्थियों को समय पर शिष्यावृती एवं छात्रवृति देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय एवं अ

शासकीय स्कूल समय पर खुलें। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सत प्रतिशत रहे। अध्यापक गण अध्यापन में नवीन तकनीकी का उपयोग करें। कमिश्नर श्री तिवारी ने अधीक्षण यंत्री पीएच ई को निर्देश दिए कि वह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन का कार्य हरदा बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले में 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग को निर्देश दिए की धरती आबा के अंतर्गत जो कार्य कराए जाने हैं वह कार्य समय पर पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने डीएलसीसी की बैठक में लखपति दीदी एवं केसीसी के प्रकरण रखने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग के कार्यों का लोकापण एवं भूमि पूजन जनप्रतिनिधियों के हाथों से ही कराए,जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद एवं समन्वय बनाकर रहें। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग में नवाचार हो रहा है तो उसे नवाचार को धारातल पर अवश्य लाएं। कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी अधिकारी नियमित रूप से भ्रमण करें और माह में एक दिन किसी भी गांव में रात्रि विश्राम कर गांव में व्याप्त समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करें। कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचारों को गंभीरता से लेने की निर्देश दिए और कहा कि यदि विपरीत समाचारों का प्रकाशन का प्रकाशन हो रहा है तो तत्काल उसका खंडन भी जारी करें। उन्होंने 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक धान खरीदी की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।



महिला बाल विकास विभाग द्वारा समझाईश देकर रोका गया बाल विवाह विदिशा ( निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम द्वारा आज विदिशा के ग्राम कागपुर की एक 16 वर्षीय नाबालिक बालिका का बाल विवाह रोकने की कार्रवाई परिजनों को समझाईश देकर की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत प्राप्त हुई थीं की ग्राम कागपुर में 16 वर्षीय नाबालिंग बालिका का बाल विवाह ग्राम रजोदा जिला झांसी के साथ होना तय हुआ है यह शादी दिनांक 30 नवम्बर 2025 को ग्राम कागपुर से होनी थी। सहायक संचालक श्री विवेक शर्मा द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विदिशा ग्रामीण परियोजना अधिकारी श्री संजय सिंह, बाल विवाह रोकथाम प्रभारी श्री मुकेश ताम्रकार, सेक्टर पर्यवेक्षक रजनी शर्मा द्वारा मौके पर पहुंचकर बालिका के परिजनों से जानकारी ली गई। बालिका की मां द्वारा आयु संबंधी दस्तावेज उपलब्ध ना कराने पर तत्काल शासकीय माध्यमिक शाला कागपुर प्रधान अध्यापक से संपर्क किया गया और स्कूल की प्रवेश पंजी में बालिका की जन्मतिथि 04 जनवरी 2009 अंकित पाई गई। बलिका के परिजनों को समझाईश और बाल विवाह प्रतिपेध अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई। परिजनों से लिखित सहमति ली गई जिस पर परिजनों ने बाल विवाह ना करने पर सहमति व्यक्त की है। बाल विवाह रोकथाम के दौरान श्रीमती पप्पी जाटव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रेखा जाटव सहयोगिका श्रीमती शीला बाई, सुशीला बाई बघेल आशा कार्यकर्ता, गीताबाई जाटव उपस्थित रहे।

## संक्षिप्त समाचार

### जिले में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु वितरित की जा रही है फूड बॉस्केट



**रायसेन (निप्र)।** रायसेन जिले को कुपोषणमुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों द्वारा अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों आदि के सहयोग से कुपोषित बच्चों को फूड बॉस्केट वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सेमरीखुर्द, देवनगर, सुल्तानगंज, केवलझिर, दाहोद सहित अन्य ग्रामों तथा निकायों में कुपोषित बच्चों को फूड बॉस्केट वितरित की गई। साथ ही महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा कुपोषित बच्चों के माता-पिता से गृह भेंट कर बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण आहार का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही घर पर ही सुगमता से उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से पौष्टिक आहार बनाने की विधि बताई जा रही है।

### बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कठपुतली और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित

**नर्मदापुरम (निप्र)।** कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के माध्यम से जन जागरूकता लाई जा रही है। तत्संबंध मेंमहिला एवं बाल विकास संचालनालय के निर्देशानुसार भोपाल के कलाकारों द्वारा कठपुतली और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं व बच्चों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु जिले की विविध परियोजनाओं में आयोजित किये जा रहे हैं।

### तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

**बैतूल (निप्र)।** तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटी बाजार में 14 नवम्बर को एवं संपन्न विद्या मंदिर भगुद्वाना में 17 नवंबर को जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान तम्बाकू नोडल अधिकारी डॉ. शुभांजलि बंसोड़, दंत चिकित्सक डॉ पूजा गंगारे एवं डॉ. अंकित मोहन द्वारा तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता व्याख्यान, शपथ ग्रहण और मौखिक स्वास्थ्य पर विद्यार्थियों को जानकारी प्रदाय की गई। साथ ही विद्यार्थियों को अपने परिवार, आस-पास पड़ोस, रिश्तेदारों को तम्बाकू से दुष्प्रभावों को बताकर तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सुभाष उ.मा. विद्यालय प्राचार्य श्रीमती आशा कटारे, संस्कार स्कूल प्राचार्य श्रीमती सुनीता पांडे एवं स्टाफ के साथ-साथ विद्यार्थी उपस्थित रहे।

### अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने आमला में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षण

**बैतूल (निप्र)।** निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण- 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने सोमवार को आमला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस मौके पर एसडीएम श्री शैलेन्द्र बड़ोनिया भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जाट ने बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं से प्राप्त किए जा रहे गणना प्रपत्रों के संग्रह एवं उनके डिजिटल अपडेट की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी मतदाताओं को प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, वहां बीएलओ आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने जनपद पंचायत एवं नगर निकाय के कर्मचारियों को भी इस प्रक्रिया में बीएलओ का सक्रिय सहयोग करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर श्रीमती जाट ने बीएलओ को समय-सीमा के भीतर सभी गणना प्रपत्र एकत्रित कर शीघ्र डिजिटल प्रविष्टि पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुनरीक्षण अभियान की गति तेज की जाए, ताकि सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सकें।



### मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग के लिए एक्सिलेंस स्कूल में पत्र लेखन कार्यक्रम आयोजित

#### स्वीप गतिविधियों के लिए खंड स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त

**विदिशा (निप्र)।**मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज एक्सिलेंस स्कूल, विदिशा में पत्र लेखन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर—इलेमेशन तथा जिले एवं विधानसभा-144 के मास्टर ट्रेनर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि बृथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। बीएलओ द्वारा

प्रदान किए जाने वाले गणना पत्रक को सही-सही भरना आवश्यक है, जिसमें दो फोटो, आधार नंबर तथा EPIC नंबर (मतदाता पहचान-पत्र) लिखना होता है। किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं करना है। इस बात पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने पत्र लेखन के माध्यम से संदेश दिया कि वे बीएलओ के कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे और मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में योगदान देंगे। उक्तृच्छविद्यालय प्राचार्य श्री खजान सिंह ने बताया कि उन्होंने विदिशा विकासखंड का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्देशानुसार विकासखंड में एक साथ टाइम टेबल जारी कर स्वीप गतिविधियों के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

## सीहोर जिले में एसआईआर की रफ्तार तेज़, कई बीएलओ बने उत्कृष्ट प्रदर्शन के उदाहरण

### कलेक्टर ने सभी बीएलओ को किया प्रोत्साहित

#### कई बीएलओ ने 98 प्रतिशत तक कार्य किया पूर्ण

**सीहोर (निप्र)।** कलेक्टर श्री बालागुरु के. के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सीहोर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिले के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित करना, भरवाकर प्राप्त करना और उसे बीएलओ एप पर अपलोड कर डिजिटलाइजेशन पूर्ण करना शामिल है। इस एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण में जिले की चारों विधानसभाओं—बुधनी, आष्टा, इछवर और सीहोर—के कई बीएलओ ने अभूतपूर्व कार्यकुशलता का परिचय दिया है। इन बीएलओ ने 04 नवंबर से 17 नवंबर की अवधि में ही 80 प्रतिशत से लेकर 98 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण क एक मिसाल कायम की है। बुधनी विधानसभा में जीवन सिंह मेवाड़ा ने 98.11 प्रतिशत, नयादास बैरागी ने 80.88 प्रतिशत और प्रेम सिंह ने 78.08 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इसी प्रकार आष्टा विधानसभा में कई बीएलओ शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में रहे, जिनमें गिरिश कुमार विश्वकर्मा 97.94 प्रतिशत, गजराज सिंह 94.61 प्रतिशत, भैरूलाल 95.80 प्रतिशत, सुश्री मधु 81.55 प्रतिशत, विक्रम सिंह 79.70 प्रतिशत और रणजीत कुमार 78.08 प्रतिशत शामिल हैं। इसी प्रकार इछवर विधानसभा में जगन्नाथ सिंह अष्टया ने 81.18 प्रतिशत और देव सिंह ठाकुर ने 77.79



प्रतिशत कार्य पूर्ण किया, जबकि सीहोर विधानसभा में ओमप्रकाश कुशवाहा ने 79.70 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। तेजी और प्रतिबद्धता के साथ किए गए इन कार्यों ने जिले में एसआईआर प्रक्रिया को तेज गति दी है। कलेक्टर श्री बालागुरु के निरंतर मार्गदर्शन में ये बीएलओ ने केवल अपनी जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा कर रहे हैं, बल्कि जिले के अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने सभी बीएलओ को प्रेरित करते हुए कहा है कि यदि इसी प्रकार सभी बीएलओ सक्रियता और समर्पण के साथ कार्य करें तो जिले का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूर्ण किया जा सकता है। इन बीएलओ की कटूट्ठ उपलब्धियां जिले के लिए गर्व का विषय हैं और यह साबित करती हैं कि टीमवर्क, प्रतिबद्धता और तकनीक के समन्वय से किसी भी बड़े कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम दिया जा सकता है।

## पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदाय किए जाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते विभाग: कलेक्टर

**नर्मदापुरम (निप्र)।** कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभागवार संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना से संबंधित आवश्यक आंकड़ों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन में सभी विभाग सतर्कता से कार्य करें जिससे पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ से लाभान्वित किया जा सके और कोई भी हितग्राही इससे वंचित न हो। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कृषि एवं उससे संबद्ध अन्य विभागों, स्वास्थ्य, रोजगार नगरीय विकास शिक्षा पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के तहत संचालित योजनाओं एवं अभियानों की गहनता से समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं तथा अन्य विषयों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कृषकों को व्यवस्थित तरीके से खाद वितरण किए जाने हेतु प्रबंधन को मजबूत किया जाए। बैठक के दौरान उपलब्ध उर्वरक एवं खाद की मात्रा के परीक्षण के उपरांत कलेक्टर ने सख्त रूप से निर्देश दिए की कृषि, सहकारिता तथा मार्केटिंग गोदाम स्तर पर भंडारित लगभग 5500 एमटी और समिति स्तर पर भंडारित



लगभग 2200 एमटी एनपीके/कॉम्प्लेक्स का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक टीएसपी/एसएसपी/एनपीके के उपयोग तथा इनकी क्षमता से किसानों को अवगत कराया जाए तथा उन्हें जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदाम में एवं समितियों के पास भंडारित एनपीके/कॉम्प्लेक्स का वितरण किसानों को किए जाने हेतु व्यापक स्तर पर इनके उपयोग के लिए प्रामाणिक जानकारी के साथ उद्धे प्रोत्साहित करें। समीक्षा के दौरान

उद्यानिकी विभाग द्वारा जानकारी दी गई की विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जिले के तीन विकासखंड केसला, माखननगर एवं नर्मदापुरम का कलस्टर तैयार कर 500 महिला कृषकों को मांग आधारित सब्जियों की खेती के हेतु जोड़ा जा रहा है। साथ ही इसके विपणन हेतु भी व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि प्राकृतिक रूप से तैयार की गई फसल का प्रदेश के शहरों में विक्रय किया जा सके तथा उद्धे आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हो।

## तंबाकू सेवन रोकने के लिए ‘जनभागीदारी और निरंतर जागरूकता’ ही सबसे प्रभावी हथियार है : कलेक्टर

### तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में नागरिकों को किया जाए जागरूक : कलेक्टर



और जिले के सभी स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों को नशा छोड़ने में सहयोग देने हेतु परामर्श व उपचार सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने तंबाकू के दुष्प्रभावों, कैसर और अन्य गंभीर रोगों के जोखिम पर आमजन को जागरूक करने के लिए पोस्टरों, रैलियों, डिजिटल मीडिया और विभिन्न आयोजन के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में तंबाकू नोडल अधिकारी डॉ नेहा सिंह ने जानकारी दी कि 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0' एवं 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम' के अंतर्गत अभी तक जिले के कुल 107 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने निर्देश दिए कि लक्ष्य अनुसार जिले के 400 स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जाए। उन्होंने जिला पंचायत के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि तंबाकू मुक्त गांव बनाने के लिए

भी निरंतर कार्य करें। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए जिला अस्पताल में कोटापा एंटर के तहत अभी तक 13 हजार रूपये की चालानी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अभी तक 180 मरीजों को निकोटीन रिप्लेसमेंट थैरेपी दी गई है। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू के दुष्प्रभावों पर विशेष सत्र, पोस्टर प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर रोक के प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाए। इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तंबाकू दुकानों का लाइसेंसिंग सिस्टम भी मजबूत किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त सुश्री वंदना राजपूत, श्री रविन्द्र परमार, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाति मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री जमील खान सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।



### पढ़ाई हमेशा कीजिए, सपने साकार होंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे

**विदिशा (निप्र)।** स्थानीय शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेड़ी में 'पुलिस कैसे बने' विषय पर आधारित छह दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ उत्साहपूर्वक हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि 'पढ़ाई हमेशा कीजिए, कुछ समय दूसरे कामों के लिए निकालिए... सपने अवश्य साकार होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा युवाओं के लिए अत्यंत उज्ज्वल करियर विकल्प है, जिसमें स्थिरता, सम्मान और समाज सेवा तीनों का अनुष्ठ संगम मिलता है। आधुनिक पुलिसिंग के क्षेत्र में तकनीक, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक विज्ञान और खुफिया विश्लेषण जैसे क्षेत्रों के विस्तार से युवाओं के लिए नए अवसर और तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं ने ग्रामीण एवं शहरी—सभी पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कर दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न पूछे। उक्तृच्छविद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा हर्षिता चौबे ने जब तैयारी की दिनचर्या के बारे में जानना चाहा, तो एसपी डॉ चौबे ने कहा पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अन्य कार्यों के लिए समय निकालिए... पढ़ाई तो हमेशा करनी ही है। कार्यशाला के पहले दिन डॉ. अमोल सोले ने व्यक्तित्व विकास विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

इसी प्रकार कलेक्टर सुश्री मीना ने निर्देश दिए कि जिले में फसलों की सिंचाई हेतु किसानों को डिग्रीस्क्लर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी इसके उपयोग, महत्व और लाभ से लगातार प्रोत्साहित किया जाए।

इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए कि जिले में स्वीकृत शासकीय गौशालाओं का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने यह निर्देश भी दिए की निर्माण अधीन गौशालाओं के निर्माण कार्य भी अविलंब पूर्ण किए जाएँ। इसी के साथ कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिए कि मुख्यमंत्री डेरी प्लस योजना के तहत तैयार करणों कि शीघ्र स्वीकृति हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कदम उठाए। इस दौरान उपसंचालक पशुपालन विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कामधेनु योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य सैचुरेटेड हो चुके हैं। बैठक के दौरान उपसंचालक मत्स्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मत्स्य पालन में उपयोग की जा रही आधुनिक तकनीक आरएएस बायोप्लेक्ताक्स एवं केज कल्चर के फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन में जिले को 27 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए जिससे जिले की मत्स्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो।



